मुख्यमंत्री ने श्रमदान कर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की

उन्होंने एल्बर्ट हॉल पर मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई

जयपुर, 14 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को एल्बर्ट हॉल से प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सफाईकर्मियों को पीपीई किट का वितरण किया। साथ ही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चैक भी दिए। शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा रामनिवास बाग में पौधारोपण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में वृहद् राजस्थान की स्थापना की गई थी। इसलिए हमने पिछले वर्ष राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस के भव्य आयोजन की शुरुआत स्वच्छता कार्यक्रम से हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जल महल की पाल एवं मानसरोवर सिटी पार्क में स्वच्छता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में एल्बर्ट हॉल से राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को एल्बर्ट हॉल से प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की।

नॉर्थ कोरिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डॉनल्ड ट्रम्प के लिए साफ संदेश था। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इससे पहले जापान ने भी उत्तर कोरिया की ओर से दागे गए एक प्रक्षेपास्त्र, जो संभवत: बैलिस्टिक मिसाइल था, के उड़ान भरने और टोक्यो के एक्सक्लूसिव इकॉनॉमिक ज़ोन (ईईज़ेड) के बाहर समुद्र में गिरने की सूचना दी थी। जब ईरान युद्ध चल ही रहा है, ऐसे समय में इन मिसाइल प्रक्षेपणों का समय अमेरिकियों, खासकर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के लिए काफी असहज करने वाला था। ऐसा लगता है कि किम जोंग उन जानबूझकर ट्रम्प को उकसा रहे हैं। इसके अलावा किम जोंग उन ने वही मिसाइलें दागी हैं, जिनसे बचाव के लिए अमेरिका अपना 'गोल्डन डोम' रक्षा तंत्र बना रहा है। इस पहल में जापान के भी शामिल होने की काफी संभावना है। इसी बीच कई रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रम्प, चीन की धरती पर आयोजित शिखर स्तर की वार्ता में किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। ट्रम्प और किम की मुलाकात की सम्भावना ईरान युद्ध के कारण और भी आवश्यक हो गई है।

दो दिन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि महानिदेशालय नौवहन भारतीय ध्वज वाले जहाजों और उन पर तैनात भारतीय नाविकों की स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए है।

अमेरिका ने ईरान के अति महत्वपूर्ण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने खाड़ी देशों की अमेरिका की मित्र सरकारों पर बमबारी जारी रखी तो वह खार्ग आईलैण्ड के ''ऑयल हैडलिंग'' ढांचे को नष्ट कर देगा।**
- **अतः चीन व रूस भी अगर खाड़ी देशों के युद्ध में शरीक हो गए और इस युद्ध की व्यापकता बढ़ी तो कहीं खाड़ी युद्ध, विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए।**

हुए, ऐसा लगता है कि अमेरिका अब ईरान की जमीन पर ''एम्फीबियन मिशन'' (जल-थल दोनों से हमला) की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वह जापान में तैनात अपनी एम्फीबियन टुकड़ियों को लगभग छह हजार मील दूर खाड़ी क्षेत्र के समुद्री पानी में ला रहा है। ईरान पर इस तरह का कोई भी एम्फीबियन हमला जमीन पर होने वाली खूनी और जबरदस्त लाड़ाइयों का सबब बन सकता है।

अमेरिका ईरान की जमीन पर लड़ने के लिए अमेरिकी मरीन सैनिकों को भेजने पर भी विचार कर रहा है। ऐसा होने पर दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या तुरंत बढ़ सकती है। इससे संघर्ष का स्तर कहीं अधिक घातक हो जाएगा।

इसके अलावा, द्वीप पर हमला करना और वहाँ मरीन सैनिकों को उतारना एक तरह के आर्थिक युद्ध की शुरूआत भी हो सकती है। खार्ग द्वीप के तेल टर्मिनल ईरान और चीन के बीच तेल व्यापार का मुख्य आधार थे।

ईरान से चीन जाने वाले अधिकतर तेल निर्यात इसी द्वीप की सुविधाओं से होते थे। ऐसे में, हो सकता है कि किसी न किसी मोड़ पर चीन भी इस मामले में दखल दे।

अमेरिका की ओर से खार्ग द्वीप पर की गई बमबारी केवल एक साधारण लक्ष्य पर हमला नहीं है। यह ईरान को उसकी सबसे संवेदनशील जगह पर चोट पहुंचाने जैसा है। खार्ग द्वीप के टर्मिनल ईरान के लगभग 80-90 प्रतिशत तेल निर्यात को संभालते थे और द्वीप पर ईरान की कुछ महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं।

ईरान के अधिकांश समुद्री तट उथले पानी वाले हैं, जहां बड़े तेल टैंकर आसानी से नहीं लग सकते। इसलिए ईरान खार्ग द्वीप की सुविधाओं का उपयोग बड़े समुद्री तेल टैंकरों को ठहराने के लिए करता है। यहीं से ये जहाज तेल भरकर दूर-दराज के देशों के लिए रवाना होते हैं।

तथापि, अमेरिका ने कहा है कि अभी तक उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और तेल से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन यदि ईरान इस क्षेत्र में अमेरिकी और उनसे जुड़े ठिकानों पर बड़े स्तर पर हमले शुरू करता है, तो अगला निशाना तेल से जुड़ी सुविधाएं भी बन सकती हैं।

ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया है, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने यह भी कहा है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में मुसलमानों को अमेरिकी और अमेरिका से जुड़े सभी स्थानों से दूर रहना चाहिए।

कुल मिलाकर, ईरान पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान यह संदेश देना चाहता है कि यदि ये देश अमेरिका से दूरी बना लें, तो वे ईरानी हमलों का लक्ष्य बनने से बच सकते हैं।

पाकिस्तान को कतई उम्मीद नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसएमडीए के तहत पाकिस्तान पर उसकी मदद करने की जिम्मेदारी बनती है।

लेकिन ऐसे बयान सऊदियों के लिए ज्यादा सुकून देने वाले नहीं हैं, जो उम्मीद कर रहे थे कि संकट की घड़ी में पाकिस्तान ठोस कदम उठाएगा।

लेकिन पाकिस्तान इस दुविधा में फँसा हुआ है कि एक तरफ उसे मिलने वाले संभावित लाभ हैं और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ एक और मोर्चा खोलने के राजनीतिक और सुरक्षा परिणाम। यह तब और मुश्किल हो जाता है, जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, बलूच स्वतंत्रता सेनानियों, पाकिस्तानी तालिबान के विद्रोहियों, अफगान तालिबान अमीरात के साथ तनाव, ईरान पर हमलों से नाराज़ शिया आबादी, और बढ़ती महंगाई व आर्थिक संकट के कारण जनता की बढ़ती नाराज़गी।

ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव, जिसे बहरीन ने पेश किया था और भारत व पाकिस्तान सहित 135 देशों ने सह-प्रायोजित किया, पाकिस्तान के लिए एक तरह का बचाव का रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान की सेना के प्रचारक इस प्रस्ताव के समर्थन को रूस और चीन के पीछे छिपकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और प्रस्ताव को वीटो भी नहीं किया। उनका तर्क है कि जब ईरान के करीबी माने जाने वाले रूस और चीन ने भी उसका खुलकर समर्थन नहीं किया, तो पाकिस्तान कैसे कर सकता था?

यह प्रस्ताव खुद इस बात का संकेत है कि ईरान किस हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। संघर्ष को व्यापक बनाने की उसकी रणनीति के पीछे भी एक खास तर्क है। लगता है कि ईरान का आकलन है कि अरब देशों में बड़े युद्ध का सामना करने की इच्छाशक्ति नहीं है और वे उसके हमलों का जवाब केवल सीमित या गैर-सैन्य तरीके से ही देंगे।

ईरान का अनुमान है कि अगर वह लंबे समय तक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाए रख सके, तो वह अपने दुश्मनों को लड़ाई खत्म करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर इसके लिए पूरे मध्य-पूर्व की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़े, तो भी वह ऐसा करने को तैयार है। यह एक बेतरतीब रणनीति है, जिसमें कम लागत वाले हथियारों को उच्च स्तर के राजनीतिक और आर्थिक दबाव के साथ इस्तेमाल करके सभी के लिए स्थिति की लागत असहनीय बनाने की कोशिश की जाती है।

समस्या यह है कि ईरान की इस रणनीति का असर केवल खाड़ी देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, ईरान ने पूरी दुनिया का गुस्सा मोल ले लिया है, यहाँ तक कि उन देशों का भी, जो पहले उसके प्रति कुछ सहानुभूति रखते थे। हालांकि चूंकि ईरान केवल अपनी सरकार ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है, इसलिए वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव उसे अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

लेकिन अगर संघर्ष के दूसरे मोर्चे खुलते हैं तो ईरान के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है।

खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर जल्दबाजी में सऊदी अरब जाना पड़ा है। चर्चाओं के अनुसार, शहबाज़ को ईरान के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने का अल्टीमेटम दिया जा सकता है।

इसमें जमीनी सैनिकों का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना की हलचल ईरान की सीमा की ओर देखी गई थी। अगर स्थिति सचमुच इस दिशा में बढ़ती है, तो यह संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश करेगा, जो कई मायनों में अधिक खतरनाक, विनाशकारी और अस्थिर करने वाला हो सकता है।

अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के आदेशों का पालन करता है, तो उसे आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे उसकी आर्थिक समस्याएँ कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कदम उठाने से जो राजनीतिक और सुरक्षा परिणाम सामने आएंगे, वे शायद किसी भी आर्थिक लाभ से कहीं ज्यादा भारी साबित हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान की किराए की सेना अपने सेवाओं के बदले कर रही है।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया और दावा किया कि सबसे पहले भाजपा समर्थकों ने गालियाँ दीं और पत्थर फेंकना शुरू किया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुँचा।

यह घटना ब्रिगेड परेड ग्राउन्ड में होने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली से लगभग आधे घंटे पहले हुई। यह रैली भाजपा की राज्यव्यापी 'परिवर्तन यात्रा' के समापन कार्यक्रम के रूप में की गई थी।

डिजिटल वॉर में अफवाहें मिसाइलों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो यह कथित असामान्यता पूरी तरह गायब हो गई।

यह घटना सूचना के इस युग के एक बढ़ते विरोधाभास को भी दिखाती है। एक ओर एआई से बने कंटैंट के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। दूसरी ओर, कभी-कभी यही जागरूकता उलटी समस्या पैदा कर देती है, जिसमें साधारण तस्वीरों या वीडियो के अधूरे फ्रेम को गलती से नकली मान लिया जाता है।

सशस्त्र संघर्ष के दौरान ऐसी गलत व्याख्याएं जल्दी ही मनोवैज्ञानिक युद्ध के बड़े कथानक का हिस्सा बन सकती हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, गुमनाम ऑनलाइन नेटवर्क और सामान्य उपयोगकर्ता भी ऐसे अपुष्ट दावों को आगे बढ़ा सकते हैं जो अनिश्चितता के माहौल में सच जैसे लगते हैं। संघर्ष में शामिल सरकारों के लिए अब सूचना प्रबंधन लगभग सैन्य रणनीति जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। लोगों तक संदेश पहुंचाना, तेजी से तथ्यों की जांच करना और डिजिटल निगरानी ऐसे जरूरी साधन बन गए हैं जिनसे उस गलत जानकारी का मुकाबला किया जा सके, जो लोगों के मनोबल को कमजोर कर सकती है या अंतरराष्ट्रीय धारणा को प्रभावित कर सकती है। नेतन्याहू से जुड़ी अफवाहें यह भी दिखाती हैं कि आधुनिक प्रपोगैंडा अक्सर पूरी तरह से मनगढ़ंत बातों के बजाय अस्पष्टता के जरिए कैसे काम करता है। कहीं बदला हुआ स्क्रीनशॉट, कहीं वीडियो का भ्रामक फ्रेम, और इसके साथ गुप्त हमलों या हत्या की कोशिशों की अटकलें, मिलकर ऐसी कहानी बना देते हैं, जो बिना ठोस सबूत के भी भरोसेमंद लग सकती है। इस स्थिति को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती है जनरेटिव ए. आई. की बढ़ती हुई काबलियत। इससे नकली लेकिन भरोसेमंद दिखने वाली तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो बनाना वास्तव में आसान हो गया है। हालांकि नेतन्याहू का वीडियो असली था, लेकिन उस पर फैला संदेह डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाता है। असल में दुनिया अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां नकली सामग्री और नकली होने के झूठे आरोप, दोनों एक साथ फैलते हैं। इसका परिणाम एक ऐसा माहौल है, जहां तस्वीरों वाले सबूतों पर से ही लोगों का भरोसा उठने लगा है। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए इससे एक नई जिम्मेदारी पैदा होती है। अब तथ्यों के वैरिफिकेशन का काम पारंपरिक रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रह सकता। इसमें डिजिटल फॉरेंसिक, चित्र विश्लेषण और तेजी से तथ्य जांच भी शामिल करनी होगी, और यह सब तब होना चाहिए, जब वायरल हो रही बातें लोगों की सोच को प्रभावित करना शुरू भी न कर पाई हों। नेतन्याहू से जुड़ी यह घटना, अफवाहें झूठी साबित होने के बाद, मामूली लग सकती है। लेकिन यह आधुनिक संघर्ष की एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है, डिजिटल युद्धक्षेत्र में लोगों की सोच मिसाइल जितनी तेजी से फैल सकती है, और गलत जानकारी उतनी ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है।

सोनम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि केंद्र लद्दाख के लोगों की अपेक्षाओं को संवाद के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908